

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]
No. 18]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2014/माघ 10, 1935
DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2014/MAGHA 10, 1935

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 231
[N.C.T.D. No. 231]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

सं.फा. 6(11) / 95—वित्त(व्यय—I) / डी.एस V / 47.—राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अनुच्छेद 10 की धारा (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, डा. एम. एम. कुटटी, प्रधान सचिव, (वित्त) को दिल्ली वित्त निगम के निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से मनोनीत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. आहुजा,
उप-सचिव-V (वित्त)

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th January, 2014

No. F. 6 (11)/95-Fin. (Exp-I)/dsV/47.—In exercise of the powers conferred under clause (b) section 10 of the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1951), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Dr. M. M. Kutty, Principal Secretary (Finance), as Director of the Board of Directors of Delhi Financial Corporation with immediate effect.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. AHUJA, Dy. Secy.-V (Finance)

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

सं.फा. 3(24) / वित्त (राज.-1) / 2013-14 / डी एस VI/145.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है।

अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (इसके पश्चात् “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 107 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या फा. 3(16) / वित्त (राज.-1) / 2013-14 / डीएस-VI / 786 द्वारा अधिसूचित दिल्ली कर अनुपालन उपलब्धि योजना 2013 के कुछ प्रावधानों, खंडों तथा प्रपत्र डीएससी-1 में संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—** (1) यह योजना दिल्ली कर अनुपालन उपलब्धि (संशोधन) योजना, 2014 कहलाएगी।
(2) सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से यह लागू होगा।
2. **दिल्ली कर अनुपालन उपलब्धि योजना, 2013** (इसके पश्चात् उक्त योजना के रूप में संदर्भित) के खंड 2(1) (घ) (i) में शब्द एवं अंक, (1), (2) तथा (3) के लिए शब्द एवं अंक “(1), (2), (3) एवं (6)” प्रतिस्थापित होंगे।
3. **उक्त योजना के खंड 3 में :—**
 - (क) उपखंड (1), (iii), के बाद निम्न सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—
“बशर्ते कि जहां कहीं भी कर की कमी किसी भी कारण से हुई हो जोकि कुल बिक्री से संबंधित न हो, देय कर, कर कमी की राशि के समतुल्य होगा।”
 - (ख) उप-खंड (2) में, “मांग” शब्द के बाद, शब्द या अंत में “ऐसे देय कर से संबंधित दंड की मांग” परन्तु स्पष्टीकरण से पूर्व शब्द ‘डीलर तथापि ऐसी माफी के आधार द्वारा वह किसी प्रकार के रिफंड का पात्र नहीं होगा’, शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा।
 - (ग) उपखंड (3) के भाग ख के अंत में निम्न सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :—
‘समय—समय पर यथा संशोधित दिल्ली (प्रलेखों के न्यून मूल्यांकन की रोकथाम) नियमावली, 2007 के अंतर्गत अधिसूचित भूमि की सर्किल दर :—

बशर्ते कि जहां वर्तमान पंजीकृत डीलर द्वारा मजदूरी तथा सर्विस के अतिरिक्त दावा से संबंधित घोषित देय कर का गलती से रिटर्न में दावा करता है तो घोषणाकर्ता ऐसे मजदूरी एवं सर्विस की गलत घोषणा पर अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार कर देगा।

बशर्ते कि आगे जहां भी कर की कमी किसी अन्य कारण से हुई हो जोकि कुल बिक्री से संबंधित न हो, तो देय कर, कर कमी की राशि के बराबर होगा:

इसके अलावा भी घोषणाकर्ता द्वारा विभिन्न संविदाओं के लिए अलग-अलग भाग (क) या (ख) के अंतर्गत देय कर की गणना की जा सकती है।

व्याख्या :— भूमि मालिक और भवन निर्माता/विकासक के बीच संविदा और भवन निर्माता एवं इच्छुक खरीदार के बीच संविदा को अलग-अलग संविदा समझा जाए।

(घ) खंड (4) में, "मांग" शब्द के बाद 'ऐसे देय करों के संबंध में दंड की मांग या शब्दों तथा अंत में परन्तु स्पष्टीकरण से पहले शब्द 'डीलर ऐसे माफी के आधार द्वारा किसी रिफंड के दावा का पात्र नहीं होगा' को सम्मिलित किया जाए।

(ङ) उपखंड (5) के बाद निम्न उपखंड सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्—

"इस खंड के उपखंड (1) या (3) में निहित (6) के होते हुए भी, जहां पंजीकृत डीलर द्वारा देय कर घोषित किया जाता है जो कर देने में असफल रहता है और 31 मार्च, 2013 से पूर्व या कर समाप्त अवधि के लिए अपना रिटर्न फाइल करता है, वह बकाया में सभी कर अवधियों के लिए अधिनियम की धारा 11 के अनुसार सकल कर देगा, और फार्म डीएससी-1 में घोषणा फाइल करने से पूर्व अधिनियम में विनिर्दिष्ट तरीके तथा इसके तहत नियत नियमों में इन करों की अवधियों के लिए अपना रिटर्न फाइल करेगा। ब्याज सहित देय करों की राशि का भुगतान कर तथा बकाया में सभी रिटर्न फाइल कर, वह कर के विलम्ब से भुगतान तथा रिटर्न के देरी से भरने (लेट फाइलिंग) के लिए अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दंडों के भुगतान से इस योजना के अन्तर्गत उन्मुक्ति के लिए पात्र होगा।

4. उक्त योजना के खंड 4 में—

(क) उपखंड (1) में शब्द व अंक, "31 जनवरी, 2014" के लिए शब्द व अंक "18 फरवरी, 2014" प्रतिस्थापित किया जाएगा और उक्त खंड के बाद नामतः निम्न परन्तुक सम्मिलित किया जाएगा—
"बशर्ते कि जहां देय कर खंड 3 के उपखंड (6) में संदर्भितानुसार घोषित है, घोषणाकर्ता पहले बकाया में अपना रिटर्न फाइल करेगा जैसाकि अधिनियम में विनिर्दिष्ट है और नियम बनाए गए हैं और फिर कर के भुगतान और रिटर्न के फाइलिंग के साक्ष्य के साथ डीएससी-1 फार्म फाइल करेगा।

(ख) उपखंड (5) में विद्यमान परन्तुक के लिए निम्न परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

बशर्ते कि जहां अपंजीकृत डीलर या वह व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 36क के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, ने इस खंड के उपखंड (1) में घोषणा की है, ऐसा डीलर/व्यक्ति पंजीकरण प्राप्त करेगा और पहली अप्रैल, 2013 से पंजीकरण की तारीख तक की अवधि के लिए सकल कर अदा करेगा और पामले के अनुसार उस अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत घोषणा प्रस्तुत करते समय नामित प्राधिकारी को फार्म डीवैट-20 में भुगतान के साक्ष्य के साथ फार्म डीवैट-16 या डीवैट-48 में रिटर्न प्रस्तुत करेगा। ऐसे डीलर/व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कर के विलम्ब से भुगतान तथा रिटर्न के न भरने (नॉन फाइलिंग) के लिए योजना के खंड 5 के अन्तर्गत उन्मुक्ति (इम्यूनिटि) का पात्र होगा।

(ग) उपखंड (8) के बाद निम्न सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(9) फार्म डीएससी-1, डीएससी-2 या डीएससी-3 में लघु परिवर्तन करने के लिए आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर जो इस योजना के लिए असंगत नहीं है ताकि ऑन लाइन फाइलिंग को सरल बनाया जा सके या अन्यथा व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट विवरण को कब्जे में लिया जाए।

5. उक्त योजना के खंड 5 के उपखंड (3) के लिए निम्न उपखंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :-

“(3) अधिकरण के स्तर पर अर्ध न्यायिक फोरम से पूर्व यह माना जाएगा कि विकल्प देने के बाद योजना को वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सभी मामलों को घोषणाकर्ता द्वारा वापस लिया जा सकता और डीएससी-1 दायर करते समय हलफनामा देगा कि डीएससी-3 के जारी होने के 15 दिनों के अंदर मामले को वापस लेगा और न्यायालय में वापसी के आवेदन की प्रति दायर करेंगे। ऐसा न कर पाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है।

6. उक्त योजना के खंड 6 के अन्त में निम्न शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“इस योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति इस योजना को लेने से पूर्व किए गए आंशिक भुगतान के लिए रिफंड का दावा करने का पात्र नहीं है यदि ब्याज या दंड की माफी के आधार द्वारा देय कर ऐसे भुगतान की राशि से अधिक हो, जैसी भी स्थिति हो।”

7. उक्त योजना के फार्म डीएससी-1 के रथान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।

फार्म-डीएससी-1

योजना के खंड 4 के उपखंड 1 के अन्तर्गत घोषणा

(फार्म भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए)

1. घोषणाकर्ता का नाम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. घोषणाकर्ता का पता

3. टेलिफोन नम्बर/मोबाइल संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. ई-मेल आईडी

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. दिन/टैन

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. क्या अतिरिक्त कर के विवरण का घोषणा पत्र आपके टर्न ओवर पर प्रभाव डालता है-

हाँ/नहीं

कर त्रुटि के कारण बताइए, यदि मद 6 का उत्तर 'न' में है

6क*. संविदा के अतिरिक्त यदि व्यापारी निर्माण कार्य में लिप्त है

* उन डीलरों के लिये जो कर देने योग्य हैं परन्तु मार्च, 2013 तक पंजीकृत नहीं हैं।

6x(i). (योजना के खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (क)) भूमि के मूल्य सहित कार्य निर्माण संविदा में लिप्त जीलर (बिल्डर सहित)-@ 1%

वित्तीय वर्ष	डीलरों का नाम	कुल बिक्री जिसमें मजदूरी तथा सर्विस और भूमि का मूल्य सम्मिलित है	कर की राशि @ 1%
	<u>देय कुल कर</u>		

6ख(ii). अन्य कार्य निर्माण संविदा (योजना के खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (ख)) @ 3%

वित्तीय वर्ष	संविदा का नाम	कुल बिक्री (Rs.)	नियम 3 के अनुसार अथवा सर्किल दर के अनुसार भूमि का मूल्य	संविदा राशि भूमि के मूल्य को छोड़कर (Rs.) (v) (iii-iv)	कर की राशि @ 3% (Rs.) (vi)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
	देय कुल कर				

431 SG/14-2

6g. लम्बित/वाद के अन्तर्गत मांगों का विवरण (कर एवं ब्याज)

6घ. देय कुल कर (6क+6ख+6ग)----- Rs.-----

६५. क्षमा योजना के अन्तर्गत आवेदन द्वारा छोड़े गये अर्थ दंडों का विवरण।

7. भूगतान का विवरण

डीलर ह्वारा जमा की गई राशि (साक्ष्य संलग्न करें)

8. कोई अनुरोध/स्पष्टीकरण :

सत्यापन

मैं (नाम स्पष्ट अक्षरों में) सुपुत्र/सुपुत्री श्री
हूँ कि मैंने दिल्ली कर अनुपालन संबंधी उपलब्धि योजना को पढ़कर समझा लिया है और मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस घोषणा पत्र और अनुलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूरी है और देय कर की राशि और इसमें दर्शाए अन्य विवरणों का सही-सही उल्लेख किया गया है।

घोषणाकर्ता/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मोहर

स्थान :

दिनांक:

(विभाग द्वारा सौंपा जाए।)

अनुदेश :

1. यह योजना दिल्ली मूल्य संबंधित कर अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई हो। इसमें उल्लिखित उपबंध ध्यान पूर्वक पढ़े जाएं (www.w.dvat.gov.in)।
2. यह फार्म विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा और हार्ड कॉपी संबंधित पदनामित अधिकारी को या इस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जाए।
3. जो घोषणा की अवधि के दौरान एक से अधिक वस्तु/निर्माण संविधा से संबंधित कोई कर बकाया है तो देय करें का प्रत्येक वस्तु/निर्माण संविधा के लिए अलग से गणना की जाए।
4. पदनामित प्राधिकारी से फार्म डी एस सी-2 में पावती प्राप्त करें।
5. घोषणाकर्ता किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये संबंधित अपर आयुक्त/संयुक्त से संपर्क कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th January, 2014

No. F. 3(24)/Fin(Rev-I)/2013-14/dsVI/145.— Whereas the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary in the interest of general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 107 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as the 'Act') , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend certain provisions, clauses and Form DSC-I of the Delhi Tax Compliance Achievement Scheme, 2013, notified vide Notification No. F.3(16)/Fin.(Rev-I)/2013-14/dsVI/786 dated the 20th September, 2013, namely:

1. Short title and commencement-

- (1) This Scheme may be called the Delhi Tax Compliance Achievement (Amendment) Scheme, 2014.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Tax Compliance Achievement Scheme, 2013 (hereinafter referred as the said Scheme) in the clause 2(1)(d)(i), for the words and figures, '(1), (2) and (3)' the words and figures '(1), (2), (3) and (6)' shall be substituted.

3. In clause 3 of the said Scheme:-

(a) after sub-clause (1)(iii), the following shall be inserted, namely:-

'Provided that wherever tax deficiency has occurred by any reason not related to turnover, the tax due will be equal to the amount of tax deficiency.'

(b) in sub-clause (2), after the word 'demand', the words, 'or the demand of penalty in relation to such tax dues.' and at the end but before the explanation, the words 'The dealer shall however not be entitled to claim any refund by virtue of such waiver.' shall be inserted.

(c) In the end of part b of sub-clause (3), the following shall be inserted, namely:-

'or circle rate of land notified under Delhi (Prevention of Under Valuation of Instruments) Rules, 2007 as amended from time to time:

Provided that where tax dues declared by an existing registered dealer pertain to excess claim of labour and services wrongly claimed in the returns, the declarant shall pay tax in accordance with rate specified in section 4 of the Act on such labour and services wrongly claimed:

Provided further that wherever tax deficiency has occurred by any reason not related to turnover, the tax due will be equal to the amount of tax deficiency:

Provided also that tax due can be calculated under part (a) or (b) differently for different contracts by the declarant.

Explanation.— The contract between landowner and the builder/ developer and that between builder and the intended buyer(s) shall be treated as different contracts.'

(d) In sub-clause (4), after the word, 'demand', the words 'or the demand of penalty in relation to such tax dues.' and at the end but before the explanation, the words
'The dealer shall however not be entitled to claim any refund by virtue of such waiver.' shall be inserted.

(e) After sub-clause (5), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

'(6) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1) or (3) of this clause, where tax dues are declared by a registered dealer who failed to pay tax and file his returns for the tax period(s) ending on or before 31st day of March, 2013, he shall pay the net tax as per section 11 of the Act for all the tax periods in default, and file his return(s) for these tax period(s) in the manner specified in the Act and rules framed there under before filing declaration in Form DSC-1. Upon payment of entire amount of tax dues with interest and filing of all returns in default, he shall be eligible for immunity under this scheme from payment of penalties specified under section 86 of the Act for late payment of tax and late filing of returns.'

4. In clause 4 of the said Scheme -

(a) In sub-clause (1) for the words and figures, '31st day of January, 2014' the words and figures '18th day of February, 2014' shall be substituted and after said clause, the following proviso shall be inserted, namely -

'Provided that where tax dues are declared as referred to in sub-clause (6) of clause 3, the declarant shall first file his return(s) in default in the manner specified in the Act and rules made there under, and then file Form DSC-1 along with proof of payment of tax and filing of returns.'

(b) For the existing proviso in sub-clause (5), the following proviso shall be substituted, namely:—
‘Provided that where an unregistered dealer or the person not registered under section 36A of the Act has made declaration referred to in sub-clause (1) of this clause, such dealer/ person shall obtain registration and pay net tax for the period from 1st day of April, 2013 to the date of registration and furnish return in Form DVAT-16 or DVAT-48, as the case may be, for that period along with proof of payment in Form DVAT-20 to the designated authority at the time of furnishing of declaration under this Scheme. Such a dealer/person shall be eligible for immunity under clause 5 of the Scheme for late payment of such tax and non-filing of return under the Act.’

(c) After sub-clause (8), the following shall be inserted, namely:-

‘(9) Commissioner, Value Added Tax may make minor modification in Form DSC-1, DSC-2 or DSC-3 not inconsistent with the scheme to facilitate online filing or otherwise by the persons to capture their specific details.’

5. For sub-clause (3) of clause 5 of the said scheme, the following sub-clause shall be substituted, namely:-

(3) All statutory appeals/revisions pending before quasi-judicial forums upto the stage of Tribunal shall be deemed to have been withdrawn once the Scheme is opted for. Further, all matters pending in the High Court and Supreme Court shall be withdrawn by the declarant and he shall file an undertaking, at the time of filing DSC-1, that the case would be withdrawn and shall further file a copy of application of withdrawal submitted in the court, within 15 days of issuance of DSC-3, failing which it will be deemed that no application has been filed under the scheme.'

6. In the end of clause 6 of the said scheme, the following shall be inserted, namely:-

‘The person availing the scheme shall also not be entitled to claim refund for the part payments made prior to availing the scheme if the amount of such payment exceeds the tax due by virtue of waiver of interest or penalty as the case may be.’

7. For Form DSC-1 of the said scheme, the following 'Form' shall be substituted, namely:-

‘FORM DSC-1

Declaration under sub-clause (1) of clause 4 of the Scheme

(Please read the instruction carefully before filling the form)

1. Name of the declarant

2. Address of the declarant

431 DS 114-3

3. Telephone No./Mobile No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Email id

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. TIN/TAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**6. Does declaration of additional Tax details affects your turnover-
Give reason for tax deficiency if answer to item 6 is 'No' -**

Yes/No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6A*. If the dealer is engaged in sales other than works contract

Financial Year	Name of Commodity	Commodity Code	Turnover (Rs.)	Rate of Tax as on the relevant date		Amount of Tax (Rs.)
				Entry/Schedule of relevant Act, if any	(%)	
Total tax due						

* for dealers who were liable to pay tax but not registered till March, 2013.

6B (i). Dealers (including builders) engaged in Works Contract including the value of land (Part (a) of sub clause (3) of clause 3 of the Scheme) - @ 1%

Financial Year	Name of project	Turnover Including labour and services and value of land	Amount of tax @ 1% (Rs.)
	Total tax due		

6B (ii). Other Works contracts [(Part (b) of sub-clause (3) of clause 3 of the Scheme)] - @ 3%

Financial Year (i)	Name of contract (ii)	Turnover (Rs.) (iii)	Value of land as per Rule 3 or as per circle rate (iv)	Contract amount excluding value of land (Rs.) (v) (iii-iv)	Amount of tax @ 3% (Rs.) (vi)
	Total tax due				

6C. Detail of demand(s) pending/ under litigation (Tax & Interest)

Act under which demand is pending (please specify)	Financial Year	Period to which demand pertains	Date of default Assessment/Assessment Order	Reference No./DCR No.	Amount assessed	Amount paid	Balance Payable	Objection No./Appeal No. (which-ever is applicable)	Supreme Court/High Court/ Appellate Tribunal/OHA
									Tax Interest Tax Interest Tax Interest
DST Act									
DVAT Act									
CST Act									
Total									

6D. Total Tax Due (6A+6B+6C)----- Rs.-----

6E. Detail of penalties to be waived of by applying under Amnesty scheme.

Act under which penalty is pending	Financial year	Tax period	Date of penalty assessment	Ref. No./DCR No.	Amount assessed	Amount paid	Objection/Appeal No. if any	Date of filing Appeal/Objection
Total								

7. Details of payment

Amount deposited by the dealer (attach proof)				Amount (Rs.)				
Sr. No.	Date of deposit	Challan No.	Name of the Bank and Branch					
Balance payable								

8. Any submissions/clarifications:

VERIFICATION

I(name in block letters) son/daughter of Shri..... solemnly declare that I have read and understood the Delhi Tax Compliance Achievement Scheme, 2013, and to the best of my knowledge and belief, the information given in this declaration and the enclosures accompanying it are correct and complete and the amount of tax dues and other particulars shown therein are truly stated.

Signature of the declarant/authorised person with stamp

Place:

Date:

(To be assigned by the department)

Date

Declaration No.

Instructions:

1. The Scheme has been notified under section 107 of the DVAT Act, 2004. The provisions contained therein may be read carefully (refer www.dvat.gov.in)
2. This Form shall be submitted online on departmental website and hard copy to be submitted to the concerned designated authority or any other officer deputed for the purpose.
3. The tax dues may be computed separately for each commodity/works contract, if the tax dues relates to more than one commodity/works contract during the period of declaration.
4. Obtain and acknowledgment from the designated authority in form DSC-2.
5. The declarant may approach the concerned Addl. Commissioner/Joint Commissioner for any clarification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

गृह-I (पुलिस) / स्थापना विभाग

अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

सं. एफ. 16/8/2013 / गृह पुलिस-I / स्था./ 5238 से 5240.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थाईकरण) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	1.	(1)	इन नियमों को दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थाईकरण) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
		(2)	यह दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
नियम 12 का संशोधन	2.		दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थाईकरण) नियमावली, 1980 के नियम 12 के सिपाही (कार्यकारी) के पद संबंधी खंड (1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— “क” पदोन्नति सूची (कार्यकारी) स्थाई सिपाही (कार्यकारी) की सूची निम्न विद्यालयी पाठ्यक्रम के लिये भेजे जाने के लिये उपयुक्त

समझी जाएगी। पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा रखने वाले स्थाई सिपाही विचार करने योग्य होंगे। सूची विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर तैयार की जाएगी, जो (1) सेवा अभिलेख (2) वरिष्ठताक्रम (3) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (4) व्यावसायिक परीक्षण से मुक्त आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाएगी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विषय होंगे:—

- (i) शारीरिक प्रशिक्षण
- (ii) प्रारम्भिक कानून एवं पुलिस का व्यवाहारिक कार्य
- (iii) सामान्य ज्ञान
- (iv) निष्पादित किए गए व्यावसायिक कार्य

40 वर्ष तक की आयु का कोई सिपाही (कार्यकारी) परीक्षण में भाग लेने के लिये योग्य होगा। चुने हुए सिपाहियों के नाम अगले एक वर्ष में उपलब्ध होने वाली प्रधान सिपाहियों की रिक्तियों को संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके वरिष्ठताक्रम के आधार पर "क" सूची में रखे जाएंगे। चुने गए सिपाही निम्न विद्यालयी पाठ्यक्रम के लिए उनकी विकित्सीय उपयुक्तता के आधार पर भेजे जाएंगे।"

HOME - I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th January, 2014

F. No. 16/8/2013/HP-I/Estt./ 5238 to 5240.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules 1980, namely:—

1. **Short title and commencement**— (1) These rules may be called the Delhi Police (Promotion and Confirmation) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Amendment of Rule 12**— In the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980, in rule 12, for clause (i) (a) relating to the post of Constable (Executive), the following shall be substituted, namely:—

"Promotion list 'A' (Executive) shall be a list of confirmed Constables (Executive) considered fit for being sent to Lower School Course. Confirmed Constables having a minimum of five years service shall be eligible for consideration. The list shall be framed on the recommendations of the Departmental Promotion Committee which shall adopt the evaluation system based on (1) Service record (2) Seniority (3) Annual Confidential reports (4) Acquittance in professional test which shall cover the following subjects:—

- (i) Physical Training
- (ii) Elementary law and police practical work
- (iii) General knowledge
- (iv) Professional work done.

A Constable (Executive) up to 40 years of age shall be eligible to appear in tests. The names of selected Constables shall be brought on list 'A' in order of their seniority keeping in view the number of vacancies in the rank of Head Constables likely to be available in the following one year. Selected Constables will be sent for Lower School Course subject to their medical fitness".

431 ४५/१४-४

सं. एफ. 16/4/2013/गृह पुलिस-1/स्था०/ 5234 से 5237—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं० फा० 24/78/68-डी०एस०एस० के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् दिल्ली पुलिस में विधि सलाहकार के पद से सम्बन्धित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1981 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा ।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी ।

2. नियम का संशोधन पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1981 के साथ संलग्न अनुसूची में

(क) कॉलम 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
01* (2014) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।

(ख) कालम 4 में, इससे सम्बद्ध शीर्षक एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“वेतन समूह एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान
देतन समूह-3, 15600—39100 रुपये (ग्रेड वेतन 5400 रुपये)”

(ग) कॉलम 6 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिये पांच वर्ष की छूट)

टीप:-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।)

(घ) कॉलम 7 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
अनिवार्य :—

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि।
- (ii) बार अथवा किसी विधिक विभाग में पांच वर्ष का अनुभव।

टीप-1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिभृत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

(ङ) कालम 10 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) और दोनों प्रकार से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(च) कालम 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

पदोन्नति की स्थिति में : वेतन समूह-2 में, 9300-3480 रुपये जमा ग्रेड पे 4600 रुपये के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सहायक विधि सलाहकार ।

टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे पदोन्नति के लिये विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति की स्थिति में (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ अर्द्ध सरकारी स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के निम्नलिखित अधिकारीगण :

1. (i) समरूप पद धारण करने वाले; अथवा
- (ii) वेतन समूह-2, वेतनमान 9300-34800 रुपये जमा ग्रेड पे 4800 रुपये में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्ष;

अथवा

(iii) वेतन समूह 2, वेतनमान 9300-34800 रुपये जमा ग्रेड वेतन 4600 रुपये में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्ष तथा

2. कालम 7 के नीचे सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।

टीप.—(भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।)

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।”

(छ) कालम 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“क” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिये), में—

(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	— अध्यक्ष
(2) मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार	— सदस्य
(3) प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), दिल्ली सरकार	— सदस्य
(4) प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली सरकार	— सदस्य
(5) पुलिस आयुक्त, दिल्ली	— सदस्य

"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण के लिये विचार करने के लिये), में:-

(1) मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार	— अध्यक्ष
(2) प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), दिल्ली सरकार	— सदस्य
(3) प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली सरकार	— सदस्य
(4) पुलिस आयुक्त, दिल्ली	— सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी. पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

No. F.16/4/2013/HP-I/Estt./5234 to 5237.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DS(S), dated 24th September, 1968, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, New Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1981, relating to the post of Legal Advisor in Delhi Police, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule.—

In the schedule to the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1981

(a) In column 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

01 *(2014) Subject to variation dependent on workload.

(b) In column 4, for the heading and the entries relating thereto, the following entry shall be substituted, namely:—

"Pay Band and Grade Pay / Pay Scale

PB-3, Rs.15600-39100 (Grade Pay Rs. 5400)"

(c) In column 6, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(d) In column 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

Essential :

- (i) Degree in Law of a recognized University.
- (ii) 5 years experience at Bar or in any Legal Department.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC/ST, if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(e) In column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment

(f) In column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

In case of promotion : Assistant Legal Advisor with three years regular service in the grade in scale of Rs.9300—34800 plus Grade Pay- Rs.4600 in PB-2.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

In case of deputation (including short term contract)

Officers under the Central / State Governments / Union Territories / Semi-Government, Autonomous or Statutory Organizations:

1. (i) holding analogous posts;

or

(ii) with two years regular service in the scale of pay of Rs.9300—34800 plus Grade Pay
Rs. 4800 in PB-2 or equivalent ;

or

(iii) with three years regular service in the scale of PB-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay—Rs. 4600
or equivalent; and

2. Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 7.

Note: (Departmental Officers in the Feeder-Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

(g) In column 12, for existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :

(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission	—Chairman
(2) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi	—Member
(3) Principal Secretary (L & J) Govt. of NCT of Delhi	—Member

431 25/14-5

(4) Principal Secretary (Home) Govt. of NCT of Delhi —Member
 (5) Commissioner of Police, Delhi- Member

“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :

(1) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi —Chairman
 (2) Principal Secretary (L & J) Govt. of NCT of Delhi —Member
 (3) Principal Secretary (Home) Govt. of NCT of Delhi — Member
 (4) Commissioner of Police, Delhi — Member

By Order and in the Name of
 Lieutenant Governor of
 National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

सं. फा. 21/60/सविव/एसटीए/2009/16.— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 68 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु राज्य परिवहन अधिकरण को निम्न रूप से पुनर्गठित करते हैं—

1. सचिव एवं आयुक्त, परिवहन	—अध्यक्ष
2. श्री संजीव झा, विधायक, बुराड़ी	—सदस्य
3. श्री मदन लाल, विधायक, कस्तूरबा नगर	—सदस्य
4. विशेष पुलिस आयुक्त, यातायात	—सदस्य
5. सचिव, एसटीए	—सदस्य—सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
 के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ज्ञानेश भारती, आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th January, 2014

No. F. 21/60/Secy/STA/2009/16.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 read with clause (41) of Section 2 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby re-constitutes the State Transport Authority for the National Capital Territory of Delhi as under :—

1.	Secretary-cum-Commissioner, Transport	—Chairman
2.	Sh. Sanjiv Jha , MLA, Burari	—Member
3.	Sh. Madan Lal, MLA, Kasturba Nagar	—Member
4.	Special Commissioner of Police, Traffic	—Member
5.	Secretary, STA	—Member- Secretary

By Order and in the Name of
the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,
GYANESH BHARTI, Commissioner (Tpt.)